small structure in Rose Garden on Ring Road, near the Indian Institute Public Administration. and five police stations are functioning temporarily on a land meant for public utilities in the Union Territory of Delhi.

(d) and (e) Steps have already been initiated to get suitable sites allotted for accommodating the ousstation forces and police stations, Police Commissioner has been asked to do advance planning and get suitable sites earmarked for accommodating them.

Supply of Arms to LTTE by Pakistan

1792. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:

SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Pakistan has been clandestinely supplying arms to LTTE from a location close to the Karachi port;

(b) if so, the steps taken by Government to take up the matter with them to stop that;

(c) whether India specifically sought tehir cooperation; and

(d) if not reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (d) The Government have seen reports linking Pakistan to the supplies of arms clandestinely to LTTE from a location close to Karachi port. Through diplomatic channels, Government have repeatedly conveyed to Pakistan the dangers inherent in supporting cross border terrorism, and have strongly urged them to cease their support to such subversive and terrorist elements.

बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा पशुओं की तस्करी

1793. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेशी-घुसपैठियों द्वारा पशुओं की तस्करी के कारण कृषि और चमड़ा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा पार कर पशुओं की तस्करी करने के कितने मामलों का पता लगाया है और उन तस्करों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) बिहार और पश्चिमी-बंगाल के पशु बाजारों से पशुओं की तस्करी रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए जानवरों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	पकड़े गए पशुओं की संख्या
1990	15689
1991	17830
1992	31587

सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए तस्करों को, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए, कस्टम प्राधिकारियों और राज्य पुलिस को सौंप दिया गया ।

(ग) भारत बंगलादेश सीमा पर जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है। इन कदमों में शामिल है :—सीमा चौकियों के बीच के अन्तराल को कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि, सघन गश्त, अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर ओ.पी. टावर खड़े करना और तटवर्ती क्षेत्रों मे बेहतर निगरानी तथा गश्त के लिए नाइट विजन डिवाइसिस, दूरबीन आदि की आपूर्ति करना।

राजभाषा संबंधी संसदीय-समिति की सिफारिशें

1794. **श्री सोमपाल :**
श्री सुरेश पचौरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केवल अंग्रेजी में आयोजित की जा रही अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए सभी भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने के संबंध में कोई सिफारिशें की है; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और मंत्रालय उस पर कब तक अनुकूल कार्रवाई करने का विचार रखता है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड 3 और 4 में संघ सरकार की सेवाओं/पदों पर भर्ती के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान के विकल्प के संबंध मे सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1960 के परिप्रेक्ष्य मे की गई है। उक्त संकल्प में संघ सरकार की सेवाओं/पदों पर भर्ती के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता: अपेक्षा करने तथा अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने का प्रावधान किया गया है। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाना है। उक्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि इन सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में पुलिस की दो नई वाहिनियों का गठन करने के लिये अनुदान

1795. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 में केंद्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दो नई वाहिनियो के गठन के लिए 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में और 50 प्रतिशत राशि ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ अब तक कोई राशि न दिए जाने के क्या कारण हैं और उक्त राशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी और

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि मध्य प्रदेश की वाहिनियों को अपने खर्चे पर अन्य राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात किया जाए और यदि नहीं तो सरकार द्वारा अपने निदेश पर राज्य को वाहिनियों की तैनाती पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति न करने के क्या कारण हैं ?